देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 27.09.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में जीएसटी और स्वदेशी जागरूकता अभियान को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य में भूकंप के प्रति सुरक्षा के लिये एक औपचारिक और सुरक्षा–केंद्रित ढांचा विकसित करने पर जोर दिया।
- तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये विज्ञान के साथ, स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक बताई।
- रुद्रप्रयाग जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से 30 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।

जीएसटी एवं स्वदेशी जागरूकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जीएसटी और स्वदेशी जागरूकता अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 22 सितम्बर से लागू नई जीएसटी दरें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका लाभ जनता को मिलने लगा है।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में अभियान को और अधिक प्रभावी बनाएँ और ग्राम सभाओं व नगर निकायों के छोटे–बड़े कारोबारियों तक पहुँचें। उन्होंने कहा कि इस अभियान से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों में भी स्वदेशी उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करने की अपील की।

बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने देहरादून में उत्तराखंड में भूकंप जोखिम मूल्यांकन और शमन से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील ज़ोन–5 में आता है, ऐसे में एक औपचारिक और सुरक्षा–केंद्रित ढांचा विकसित कर, संभावित मानवीय व आर्थिक क्षति को न्यूनतम करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में नियमित रूप से भूकंप मॉक ड्रिल आयोजित करने और एक निर्धारित दिन पर ''भूकंप जागरूकता दिवस'' मनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के साथ विस्तृत समझौता ज्ञापन करे, ताकि भिन्न–भिन्न गतिविधियों की ज़िम्मेदारी विशेषज्ञ संस्थानों को सौंपी जा सके। भवन निर्माण के लिए भूकंप की दृष्टि से आवश्यक मापदंड निर्धारित करने की बात कहते हुए मुख्य सचिव ने सीबीआरआई के साथ भूकंपरोधी भवनों के निर्माण के लिये एमओयू की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

बैठक

श्रम आयुक्त पी.सी. डुम्का की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मकारों के पंजीकरण को लेकर देहरादून में एक बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि मनरेगा में 16 लाख तीन हजार श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग छह लाख सात हजार सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

बैठक में सहमति बनी कि जो मनरेगा श्रमिक वर्ष में 90 दिन कार्य करते हैं, उनका पंजीकरण और श्रमिक कार्ड, विकास खंड कार्यालय स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बीडीओ स्तर पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मनरेगा के आवेदन खंड विकास अधिकारी अनुमोदित करेंगे, जबकि भवन व निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के आवेदन संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी से अनुमोदित होंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि बीडीओ कार्यालय के पास दो सीएससी केंद्र चिह्नित कर श्रमिकों का ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा, ताकि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

फटकार

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि यह परियोजना तय समय पर पूरी होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण परियोजना है और जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं है। उन्होंने एसडीएम सदर और लोक निर्माण विभाग के एक्स.ई.एन को नोडल अधिकारी नामित किया, जो रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर गार्डर ब्रिज प्लेसमेंट और निर्माण कार्य की निगरानी करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह परियोजना सहारनपुर रोड पर वाहनों का दबाव कम करने और जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई थी। इससे भंडारीबाग को रेसकोर्स चौक से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रिंस चौक और हरिद्वार रोड के बीच यातायात सुगम होगा।

पर्यटन कार्यक्रम

विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कंडोलिया मैदान, पौड़ी में तीन दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने की। इस मौके पर हॉट एयर बैलून, साइक्लिंग रैली और स्वच्छता रैली आयोजित हुईं, जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं, स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य का अनुभव कराता है। उन्होंने अपील की कि पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखें और 'अतिथि देवो भव' की भावना अपनाएँ।

सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन

दून विश्वविद्यालय में 12वें सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन का भाषा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र, देश को 60 प्रतिशत जल उपलब्ध कराता है, लेकिन यहां बार–बार जलवायु आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रकृति–संलग्न और जन–केंद्रित विकास आवश्यक है।

श्री उनियाल ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का आधार हैं, लेकिन स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के बिना यह सफल नहीं हो सकता। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में अर्पण सामग्री से ग्रामीणों को रोजगार मिलने, पिरुल संग्रह से जंगलों में आग की घटनाओं में कमी और ईको–होमस्टे पहलों को पलायन रोकने में कारगर बताया।

सम्मेलन में लगभग 250 प्रतिभागियों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों ने हिस्सा लिया। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

रोजगार मेला

रुद्रप्रयाग जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से आगामी 30 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला जिला सेवायोजन कार्यालय, मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग में आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।

जिला सेवायोजन अधिकारी सुशील चमोली ने बताया कि रोजगार मेले में 250 रिक्तियां हैं। मेले में प्रतिभाग करने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं से लेकर स्नातक, आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक तक निर्धारित है। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों पर मासिक वेतनमान ग्यारह हजार रुपये से चालीस हजार रुपये तक निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंकपत्र,

बायोडाटा और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 30 सितंबर को सुबह 10 बजे जिला सेवायोजन कार्यालय, रुद्रप्रयाग में उपस्थित हो सकते हैं।

राहु मंदिर

पौड़ी जिले की जिलाधिकारी स्वाति. एस. भदौरिया की अध्यक्षता में राहु मंदिर के जीर्णोद्धार और मास्टरप्लान को लेकर बैठक आयोजित हुई। इसमें मंदिर समिति, व्यापार मंडल, स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मंदिर परिसर और घाटों के सौंदर्यीकरण की योजना प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मंदिर की ऐतिहासिकता को संरक्षित रखते हुए इसे विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसके तहत वेटिंग हॉल, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले, विश्राम स्थल, प्याऊ और भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण और सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्य स्थानीय स्थापत्य शैली में हों और गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। मंदिर को हेरिटेज स्थल के रूप में विकसित करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि समिति और स्थानीय लोग विकास कार्यों की सतत निगरानी करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि राहु मंदिर जिले की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। इसे आधुनिक सुविधाओं से विकसित कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन की पहचान दिलाई जाएगी।

काउंसलिंग स्थगित

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल ने 27 सितंबर को प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025–2027 की काउंसलिंग स्थगित कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि इस दिन डीएसबी परिसर में छात्र संघ महासंघ चुनाव आयोजित होने के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। काउंसलिंग की नई तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी और छात्रों को समय पर सूचित किया जाएगा।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर——

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र नकल मामले में हो रही एसआईटी जांच की खबर हिन्दुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है।

जीएसटी बचत उत्सव के तहत चलाए जा रहे अभियान की खबर भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से ली हैं। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के हवाले से लिखा– जीएसटी दरों में कमी से समाज के हर वर्ग को मिल रहा लाभ।

एक अन्य ख़बर पर अमर उजाला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखा है– सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध।

प्रदेश में चल रहे स्वस्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान पर अमर उजाला की सुर्खी है– स्वास्थ्य शिविरों में अब तक दो दशमलव सात–छह लाख की कैंसर की जांच।